पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
आपराधिक विविध संख्या 11188/2024

थाना से उत्पन्न. कांड संख्या-1777 वर्ष-2023 थाना-उत्पाद थाना जिला-मुजफ्फरपुर

कलाम अंसारी, पुत्र जहरिल अंसारी, ग्राम-नवादा, थाना-बिशुनगढ़, जिला-हजारीबाग, राज्य-
झारखंड

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. विपरीत पक्ष/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अनीश कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री मुजतबाउल हक, जीपी-12
श्री मनीष कुमार, एसी से जीपी-12
श्री उपेन्द्र कुमार, एपीपी

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016—धारा 60—याचिकाकर्ता का ट्रक अधिनियम, 2016 के तहत जब्त किया गया था—विशेष मद्यनिषेध न्यायालय ने जब्त ट्रक को छोड़ने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया—किसी भी न्यायालय की अधिकारिता जब्त वाहन या अन्य वस्तुओं के संबंध में कोई आदेश पारित करने के लिए वर्जित है—जब्त की गई सामग्री जब्त की जा सकती है—विशेष मद्यनिषेध न्यायालय के पास अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत जब्त किए गए वाहन के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है—इस प्रकार, विशेष मद्यनिषेध न्यायालय ने ट्रक को छोड़ने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है—आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं है और न ही अदालत की गलती है—आक्षेपित आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज किया गया ।

(पैरा 16)

2020 (1) बी.एल.जे. 706—निर्भर किया गया

2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 851; ए.आई.आर. ऑनलाइन 2024 पटना 73; 2024

(3) बी.एल.जे. 163; 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 850: 2024 (2) बी.एल.जे. 341:
2024 (1) पी.एल.जे.आर. 905; 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 849: ए.आई.आर.
ऑनलाइन 2024 पटना 177: 2024 (3) बी.एल.जे. 130: 2024 (1) पी.एल.जे.आर. 905;
2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 853 : ए.आई.आर. ऑनलाइन 2024 पटना 127: 2024
(2) बी.एल.जे. 465: 2024 (2) पी.एल.जे.आर. 184—संदर्भित किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक : 22-05-2024

वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर की गई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (उत्पाद शुल्क), कोर्ट संख्या-II, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 11.09.2023 को आबकारी थाना केस संख्या 1777/2023 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए), 32(2) और 48 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 को रद्द करने और अलग रखने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से जब्त ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर JH-10CR-7110, चेसिस नंबर MC2ERHRCOPDB05988, इंजन नंबर E446CDPO63534 को याचिकाकर्ता के पक्ष में छोड़ने के लिए दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 60 के तहत वर्जित है मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जब्त वाहन को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।

2. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के अनुसार, संबंधित वाहन को पुलिस ने 2847 लीटर शराब के साथ जब्त किया था और तत्पश्चात, मालिक, जो कि यहां याचिकाकर्ता है, और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम की धारा 30 (ए), 32 (2) और 48 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आबकारी पुलिस थाना कांड संख्या 1777/2023 दिनांक 11.09.2023 को दर्ज किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील ए.पी.पी. को सुना गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पास वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज हैं, जो दर्शाते हैं कि वह वाहन का मालिक है। उन्होंने आगे दलील दी कि उनके पास ट्रक में भरी गई शराब के संबंध में भी वैध दस्तावेज हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत विद्वान विशेष न्यायालय को वाहन को छोड़ने का अधिकार है।

5. हालाँकि, राज्य के लिए विद्वान ए.पी.पी. ने यह कहते हुए विवादित आदेश का बचाव किया कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 60 के तहत जब्त किसी भी वाहन को छोड़ने के संबंध में विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वाहन जब्त किया जाना उचित नहीं है, इसलिए, इस आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब्त वाहन बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 56 के तहत जब्त किए जाने योग्य है। हालांकि, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क नियम, 2021 के नियम 12 ए के तहत, जैसा कि 2022 में संशोधन के बाद लागू है, अधिनियम, 2016 की धारा 57 बी के साथ पढ़ा जाए, याचिकाकर्ता नियमों में निर्धारित जुर्माना के भुगतान के बाद वाहन को मुक्त कराने के लिए स्वतंत्र है।

6. इससे पहले कि मैं प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करूं पक्षकारों के बीच, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ देना समीचीन होगा।

7. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 60, 2016 के अनुसार, अधिनियम के तहत जब्त वाहन या अन्य वस्तुओं के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने के लिए किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक है। यह इस प्रकार है:-

“60. अधिहरण में अधिकारिता का वर्जन.- जब कभी कोई शराब, सामग्री, स्टिल, बर्तन, औजार या तंत्र या कोई भी पात्र, पैकेज, कोई भी

पशु गाड़ी, जहाज, या अन्य किसी अपराध को करने में उपयोग किया गया वाहन जब्त कर लिया जाता है या इस अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संबंध में कोई भी न्यायालय, किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी वर्तमान में लागू अन्य कानून, बनाने का अधिकार क्षेत्र ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।”

8. अधिनियम की धारा 56 में जब्त वाहनों के साथ-साथ अन्य जब्त वस्तुओं को भी जब्त करने का प्रावधान है। इस प्रकार है:-

“56. जब्त वस्तुओं की जब्ती:- बावजूद इसके धारा 57 बी में निहित कुछ भी, जब भी कोई अपराध इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया जाता है, तो कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी ऐसी वस्तुओं को जब्त कर सकता है जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर।

(2) ऐसी मदों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं -

- (i) कोई परिसर या उसका कोई भाग;
- (ii) कोई पशु, वाहन, जलयान या सवारी;
- (iii) कोई भी शराब या नशीला पदार्थ;
- (iv) मामले से संबंधित कोई अन्य मद;

बशर्ते, जहां धारा 57 में उल्लिखित बातें हों, नष्ट किया जा सकता है, तो कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी उनके समक्ष उसी को जब्त करने की विनाश से पहले आवश्यकता नहीं है।

(3) राज्य सरकार आवश्यक निर्देश, दिशानिर्देश, विनियम और निर्देश जारी कर सकेगी जब्ती, तलाशी, विनाश और जब्ती का तरीका और ढंग

के संबंध में ।”

9. 2022 में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 57 बी में यह प्रावधान है कि निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया कोई भी वाहन, जिसे किसी पुलिस अधिकारी या उत्पाद शुल्क अधिकारी ने जब्त कर लिया है, उसे कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दंड का भुगतान करने पर छोड़ा जा सकता है। यह धारा इस प्रकार है:-

“57 बी. ऐसी चीजें या परिसर जिनपर जुर्माना हटाया जा सकता

है.- (1) कोई भी पशु, वाहन, जलयान या अन्य जिसे इस दंडनीय अपराध को करने के लिए इस्तेमाल किया गया इस अधिनियम के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है उसे कलेक्टर द्वारा रिहा किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे जुर्माने का भुगतान करने पर।

(2) कोई परिसर या उसका कोई भाग किसी दंडनीय अपराध के लिए उपयोग किया गया हो इस अधिनियम के तहत जिसे किसी भी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी ने जब्त कर लिया गया है उसे कलेक्टर द्वारा रिहा किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे जुर्माने का भुगतान करने पर।

(3) यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है, तो कलेक्टर उक्त पशु, वाहन, जहाज या अन्य परिवहन और परिसर को जब्त करने की कार्यवाही करेगा, धारा-58 के तहत।

स्पष्टीकरण 1.- अभियुक्त को यह अधिकार नहीं होगा कि उसके द्वारा आवश्यक जुर्माने की राशि का भुगतान करने पर उसका वाहन, वस्तु या

परिसर मुक्त कर दिया जाएगा। कलेक्टर, एक रिपोर्ट के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी द्वारा, किसी कारणवश लिखित रूप में दर्ज किये जाने के बाद भी, उक्त वाहन, वस्तु या परिसर को रिहा करने से इनकार कर सकता है और आगे जब्ती और नीलामी/विनाश कर सकता है।

स्पष्टीकरण 2.-यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना अदा करता है तो जैसा कि अधिसूचित किया गया है कलेक्टर इस संशोधन के लागू होने की तारीख से, जब्ती की कार्यवाही को बंद कर दे और ऐसे वाहन, सवारी या परिसर को छोड़े।

स्पष्टीकरण 3.- ऐसी रिहाई विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के परिणाम को, यदि कोई हो, प्रभावित नहीं करेगी।”

10. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 95 के अंतर्गत बिहार सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 95 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद नियम, 2021 बनाया गया है। संशोधन के माध्यम से 2022 में सम्मिलित नियम 12A में जुर्माना अदा करने पर वाहन, सवारी आदि को छोड़ने का प्रावधान है। यह नियम इस प्रकार है:-

“12 ए. वाहनों, परिवहन आदि को रिहा करना जुर्माने का भुगतान पर.- (1) यदि कोई वाहन, सवारी, जहाज, जानवर आदि किसी पुलिस या आबकारी अधिकारी द्वारा जब्त किया गया हो अधिनियम के तहत, तो अधिनियम की धारा 57 बी (1) के अनुसार, कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी वाहन या सवारी आदि के मालिक द्वारा

फार्म IV द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर जुर्माने के भुगतान के बाद उक्त सवारी या वाहन को कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी के आदेश पर रिहा किया जा सकता है।

उसके द्वारा बशर्ते, जहां वाहन के मालिक का पता लगाना संभव न हो या मालिक दावा करने नहीं आ रहा हो, वाहन जब्त होने की स्थिति में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जब्ती की तारीख से 15 दिन तक प्रतीक्षा करने के पश्चात, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहन को जब्त करने और नीलाम करने की कार्यवाही करेगा।

(2) जुर्माने की राशि कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। जुर्माना लगाते समय, उन्हें बरामद मादक पदार्थ की मात्रा, वाहन मालिक की संलिप्तता और वाहन के नवीनतम बीमा मूल्य को ध्यान में रखना होगा। किसी भी स्थिति में, जुर्माना वाहन के बीमित मूल्य के 10% से कम और 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बीमित मूल्य, बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित वाहन का मूल्य है। जहां, बीमित मूल्य उपलब्ध नहीं है या कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वाहन का मूल्यांकन कम किया गया है, तो वह जिला परिवहन अधिकारी से मूल्यांकन करवाएगा। किसी भी मामले में, कलेक्टर जब्ती की तारीख से 15 दिनों से अधिक इंतजार नहीं करेगा और यदि इस अवधि के दौरान, आरोपी/मालिक जुर्माना नहीं चुकाता है, तो वह जब्ती/नीलामी की कार्यवाही करेगा।"

(3) उपर्युक्त के होते हुए भी, यदि पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस

बात से संतुष्ट हो जाता है कि वाहन या सवारी को छोड़ना लोकहित में नहीं होगा, तो वह उक्त वाहन या सवारी को जब्त करने और उसके बाद उसकी नीलामी/निपटान की कार्यवाही करेगा।

(4) जहां वाहन ऐसा है कि उसका मूल्यांकन/बीमा संभव नहीं है, वहां कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ऐसा जुर्माना लगाएगा जैसा वह उचित समझे। ऐसा जुर्माना लगाते समय कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा को ध्यान में रखेगा।

(5) ऐसा जुर्माना, विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम की परवाह किए बिना, वापस नहीं किया जाएगा।

(6) वाहन/सवारी का स्वामी, वाहन/सवारी को छोड़े जाने के पश्चात, प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर वाहन/सवारी को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण. वाहनों की जब्ती/नीलामी के सभी लंबित/चल रहे मामलों में, कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी मौजूदा मालिक को उपरोक्त जुर्माना अदा करने और वाहन को मुक्त कराने का अवसर दे सकते हैं। स्वामित्व के बारे में संतुष्टि होने और ऐसे जुर्माने का भुगतान करने पर, चल रही जब्ती/नीलामी कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है और वाहन को मुक्त किया जा सकता है।”

11. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 60 में उल्लिखित जब्त वाहन या अन्य वस्तुओं के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने के लिए किसी भी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिनियम के तहत जब्त की गई सामग्री

अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जब्त की जा सकती है।

12. हालाँकि, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियम, 2021 के नियम 12 ए के अनुसार, याचिकाकर्ता को नियमों के तहत उत्पाद अधिकारियों द्वारा तय किए गए जुर्माने के भुगतान पर वाहन को छोड़ने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता है।

13. यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी क़ानून में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक के प्रावधानों के बावजूद, उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया गया है। यहां, **सुरेश साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2020(1) बीएलजे 706** का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 60 के मद्देनजर विशेष उत्पाद न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था। यहां, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 60 के आलोक में, विशेष उत्पाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसा प्रतिबंध लागू नहीं होता है। **सुरेश साह मामला (उपर्युक्त)** का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-

“28. भले ही वाहन उत्तरदायी न हो यदि वाहन जब्त करने के लिए धारा 60 के तहत निषेधाज्ञा लागू होती है तो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के पास वाहन को छोड़ने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता के प्रयोग में ऐसा निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसी शक्ति का प्रयोग मौजूदा भयावह स्थिति में किया जाना आवश्यक है.....।”

14. **सुनैना उर्फ सुनैना बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2024**

एससीसी ऑनलाइन पैट 851, एआईआर ऑनलाइन 2024 पैट 73, 2024 (3) बीएलजे 163) में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आगे माना है कि यदि वाहन की जब्ती या जब्ती के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो आबकारी अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी वाहन की जब्ती या जब्ती मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन होगा और वाहन का मालिक न केवल वाहन की रिहाई का हकदार होगा, बल्कि ऐसी जब्ती या जब्ती के कारण मुआवजे का भी हकदार होगा। निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-

“27. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम पाते हैं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत वाहन की जब्ती और जब्ती के लिए दो पूर्वापेक्षाएँ - शराब या मादक पदार्थ ले जाने / परिवहन में वाहन का उपयोग और अपराध करने में वाहन के मालिक की सहमति या मिलीभगत - पूरी नहीं हुई हैं। नतीजतन, विचाराधीन वाहन अधिनियम के तहत जब्त और जब्त किए जाने योग्य नहीं है।

28. इसलिए, विवादित आदेश मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। यह संविधान के अनुच्छेद 300ए में दिए गए संपत्ति रखने के याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 ए में दिए गए हैं। कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित करने पर रोक लगाता है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम किसी भी तरह से अधिकारी को मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों में मोटरसाइकिल को जब्त करने या जब्त करने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए, विचाराधीन मोटरसाइकिल की जब्ती और जब्ती किसी भी कानून के अधिकार के

बिना है। जब्ती आदेश, तदनुसार रद्द करने योग्य है। याचिकाकर्ता, जिसके संपत्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, पर्याप्त मुआवजे का हकदार है। वह जबरन मुकदमेबाजी के दौरान खर्च और उत्पीड़न के कारण मुआवजे का भी हकदार है।

29. इसलिए, जब्ती (उत्पाद शुल्क) वाद संख्या 700/2020 में गोपालगंज के जिला कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 19.11.2021 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। गोपालगंज के जिला कलेक्टर को तत्काल मोटरसाइकिल जारी करने का भी निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाता है। मुआवजे का भुगतान आदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।”

15. इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मामलों में भी इसी प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं:-

(i) बिनीत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,

(2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 850, 2024 (2) बीएलजे 341,

2024 (1) पीएलजेआर 905)

(ii) शांति देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,

(2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 849, ए आई आर ऑनलाइन 2024

पैट 177, 2024 (3) बीएलजे 130, 2024 (1) पीएलजेआर 905)

(iii) अमरजीत यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,

(2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 853, ए आई आर ऑनलाइन 2024

पैट 127, 2024 (2) बीएलजे 465, 2024 (2) पीएलजेआर 184)

16. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि विशेष उत्पाद न्यायालय को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त वाहन के संबंध में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अतः विशेष उत्पाद न्यायालय याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करना सही है। इसमें कोई अवैधानिकता या अनुचितता नहीं है यह न तो किसी प्रकार का अन्याय है और न ही किसी प्रकार का अन्याय है। तदनुसार, वर्तमान याचिका को विवादित आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज किया जाता है।

17. तथापि, यदि याचिकाकर्ता को ऐसा परामर्श दिया जाए तो वह स्वतंत्र है। यदि याचिकाकर्ता का मानना है कि उसका वाहन उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जब्त किए जाने योग्य नहीं है, तो वह इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। लेकिन यदि याचिकाकर्ता का मानना है कि उसने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उसका वाहन जब्त/जबती योग्य है, तो वह अधिनियम के तहत जुर्माना अदा करने पर वाहन को मुक्त करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों के समक्ष उचित आवेदन कर सकता है और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/ शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।